जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका समाचार पत्रिका

।। माह – फरवरी 2021 ।। अंक–07 ।। केवल आंतरिक वितरण हेतु।।

अन्दर के पृष्ठों में...

दीदी की रसोई
सफलता एवं सकारात्मकता की बानगी
(पृष्ठ – 02)

"दीदी की नर्सरी" से
जीवन में आई हरियाली
(पृष्ठ – 03)

जल–जीवन–हरियाली अभियान से
बदल रहा बिहार
(पृष्ठ – 04)

दीदी की रसोई : जीविका एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार के समन्वय से जीविका दीदियों की अनूठी पहल

जीविका और स्वास्थ्य विभाग बिहार की एक अनूठी पहल है "दीदी की रसोई"। इसके माध्यम से 'उद्यमी महिला : स्वावलंबी महिला' के सपनों को साकार करते हुए ग्रामीण महिलाएँ पारिवारिक आय की वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

"दीदी की रसोई" के अंतर्गत जीविका दीदी सामाजिक बदलाव के अतिरिक्त आर्थिक विकास की ओर निरंतर गतिमान हैं। दीदियों द्वारा अस्पताल में अन्त :वासी मरीजों को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस गतिविधि से स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और जीविका दीदियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।

"दीदी की रसोई" जीविका संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से संचालित एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें व्यवसाय से सम्बंधित, इच्छुक एवं प्रशिक्षित 06–10 जीविका दीदियाँ सम्मलित होती हैं। जीविका द्वारा क्षमतावर्धन एवं उद्यमिता विकास में सहयोग दिया जाता है। इस में काम करने वाली दीदियाँ, जीविका द्वारा संपोषित स्वयं सहायता समूह से जुडी रहती हैं। "दीदी की रसोई" का मालिकाना हक संबंधित सामुदायिक संगठन के पास रहता है जिसके तहत सामुदायिक संगठन और "दीदी की रसोई" तथा सामुदायिक संगठन और अस्पताल प्रबंधन के बीच एकरारनामा होता है।

"दीदी की रसोई" के संचालन हेतु सर्वप्रथम सामुदायिक संगठन से चिन्हित सदस्यों का साक्षात्कार कर उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान दीदियों का चयन विभिन्न मानकों पर खरा उतरने पर किया जाता है।

पेशेवर प्रशिक्षण हेतु केरल की विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी ''कुदुम्बश्री'' के साथ एकरारनामा किया गया है। ''कुदुम्बश्री'' द्वारा दीदियों को अनेक प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसे–ग्राहकों के साथ संचार, स्वच्छता और रखरखाव, संकट प्रबंधन, कच्चे माल की खरीद की तकनीक, मीनू योजना, लेखा और पुस्तक संधारण, लागत और कई अन्य प्रासंगिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर अंतिम उद्यमियों सह भागीदारों को दीदी की रसोई की स्थापना और चलाने के लिए चुना जाता है।

वर्तमान में "दीदी की रसोई" बिहार के 8 जिलों सफलतापूर्वक संचालित है। इसके अतिरिक्त पटना में अवस्थित रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया के परिसर एवं डी.एम.आई. पटना के छात्रावास में भी यह संचालित है।

"दीदी की रसोई" से मरीजों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा रहा है जिससे जनसाधारण में अस्पताल प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

जीविका दीदियों की इस पहल को सराहते हुए दिनांक 12 जनवरी 2021 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य के सभी जिला अस्पतालों तथा अनुमंडलीय अस्पतालों के अन्त :वासी रोगियों को उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा दीदी की रसोई की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

"दीदी की रसोई" सफलता एवं सकारात्मकता की बानगी

बक्सर के जिला स्तरीय सदर अस्पताल में जीविका दीदियों द्वारा 'दीदी की रसोई' के माध्यम से इंडोर मरीजों के साथ ही आउट डोर में भी आगन्तुकों को उचित दर पर शुद्ध एवं पोषक नाश्ता–खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। हिम्मत जीविका महिला ग्राम संगठन, बक्सर सदर अंतर्गत दीदी की रसोई फरवरी 2019 से ही लोगों के सेवार्थ संचालित है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों को अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित मीनू के तहत सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय–बिस्किट और रात का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य में खाना बनाने और परोसने में पारंगत छह जीविका दीदियाँ सुबह से लेकर रात तक रोस्टर के तहत सेवारत हैं। इसके साथ ही आगंतुको और अस्पताल कर्मियों को भी उचित दर पर नाश्ता–चाय एवं भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर मीटिंग और प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता एवं भोजन उचित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना काल में भी 'दीदी की रसोई' द्वारा जिले के दस से ज्यादा कोरोंनटाइन सेंटर पर प्रतिदिन लगभग डेढ़ सौ लोगों को मानक के अनुरूप नाश्ता एवं खाना उपलब्ध कराया गया और उस अवधि में इस पहल को लगभग दो लाख रूपये का मुनाफा भी हुआ। सदर अस्पताल में स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जीविका दीदियों को उनकी रूचि के अनुरूप रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।

पेड़ लगाने से बढ़ेगी हरियाली और परिवार में आएगी खुशहाली

सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड अन्तर्गत थुम्हा ग्राम पंचायत की रहने वाली संगीता देवी अंबिका जीविका महिला ग्राम संगठन अर्न्तगत ग्राम संसाधन सेवी (वीआरपी) के रूप में कार्यरत है। संगीता देवी को पेड़–पौधों से खूब लगाव है। उसने अपने घर के पिछले हिस्से में आम, अमरूद, कटहल, केला, नींबू, सहजन, बांस समेत अनेक तरह के फलों एवं इमारती लकड़ियों के पेड़ लगाए हैं। इससे उसके घर के आस–पास हमेशा हरियाली बनी रहती है साथ ही सीजन पर आम–अमरूद–केले जैसे फल भी उसके घर में आसानी से उपलब्ध होते हैं। वह न केवल स्वयं पेड़–पौधे लगाती है बल्कि वह जीविका दीदियों को भी पेड–पौधे लगाने को प्रेरित करती है। वह हर किसी विशेष अवसर पर अपने घर में पेड़ लगाकर उस पल को यादगार बनाती है। संगीता दीदी इसी जुनून की वजह से समूह की दीदियों के बीच 'हरियाली दीदी' के नाम से जानी जाती है। संगीता देवी ने इस वर्ष मनरेगा की मदद से अपनी जमीन में पौधारोपण किया है। मनरेगा योजना के तहत मिली सहायता से उसने अपने 10 कट्ठा खेत में तकरीबन 40–50 आम के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा खेत के चारों और सहजन एवं इमारती लकड़ियों के पौधे लगाए हैं। मनरेगा योजना से मिली सहायता राशि संगीता देवी बागवानी करने में काफी मदद मिली है। वह बताती है कि सरकार पेड़–पौधे लगाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है, जिसका जीविका दीदियों का लाभ उठाना चाहिए। वह बताती हैं कि पेड़ लगाने से न केवल हमारी धरती पर हरियाली बढ़ेगी बल्कि यह गरीब परिवारों के लिए किसी 'फिक्सड डिपॉजिट' से कम नहीं है। दस–पंद्रह वर्षों के बाद ये पेड़ बड़े होकर अच्छी कीमत देते हैं। इस प्रकार यह गरीब परिवारों को भविष्य में अच्छे पैसे प्राप्त करने का माध्यम हो सकता है। इन्हीं कारणों से संगीता देवी 'हरियाली दीदी' के रूप में जीविका दीदियों को पेड़–पौधे लगाने हेतु प्रेरित कर रही है।

"दीदी की नर्सरी" से जीवन में आई हरियाली

पूर्णियाँ जिले के जलालगढ़ प्रखंड के चक गाँव की निभा कुमारी ने मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना से पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ अपने को आर्थिक रूप से सशक्त करने में सफलता पाई है। 25 वर्षीय निभा कुमारी दिनांक 20.06.2017 को लक्ष्मी बाई जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर समूह द्वारा संचालित गतिविधियों में भाग लेने लगीं। समूह से जुड़ने के कुछ माह बाद आमदनी बढाने हेतु घर के पास में ही पौधशाला में पौध तैयार कर बेचने का कार्य प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के तहत निर्मल जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ अंतर्गत "दीदी की नर्सरी" के संचालन हेतु जीविका द्वारा निभा कुमारी का आवेदन पूर्णियाँ वन प्रमंडल कार्यालय को दिया गया एवं "दीदी की नर्सरी" संचालन के लिए उनका चयन हो गया। विभाग ने अग्रिम राशि के रूप में 88 हजार रुपये निभा कुमारी के बैंक खाते में दिया। उसने पौधशाला में 20 हजार से अधिक पौधे तैयार किए। 2020 के अगस्त माह में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने उनकी "दीदी की नर्सरी" से महोगनी एवं एमसोल के कुल 19900 पौधे की खरीद किया। निभा कुमारी को विभाग से प्रति पौधा 11.50 रुपये की दर से कुल 2,28,850 रुपये प्राप्त हुए। सभी खर्च के बाद निभा कुमारी को "दीदी की नर्सरी" से पिछले एक वर्ष में 1,28,850 रुपये का लाभ हुआ है। इसके अलावा आस–पास के किसान उनकी पौधशाला से पौधें खरीदते हैं। अन्य लोगों को रोजगार देने के साथ ही अब वह प्रति माह 10,000 से 12,000 रुपये पौधशाला के व्यवसाय से कमाई कर रही हैं।

"दीदी की नर्सरी" आत्मविश्वास की एक नई झलक

हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान होती है। ललिता देवी के चेहरे पर आज एक आत्मविश्वास की चमक दिखती है। देवी जीविका स्वयं सहायता, कटरमाला, गोरौल (वैशाली) से वर्ष 2014 में जुड़ने के बाद ललिता देवी ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा। वे बताती हैं कि उनके जीवन में बदलाव तो शुरू हो गया था परन्तु जब उन्होंने 2020 में नर्सरी की शुरुवात की तब वे आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो गयीं। ललिता देवी बताती हैं कि जीविका–गोरौल के माध्यम से मुझे पता चला कि प्रखंड में वन विभाग के सहयोग से दो नर्सरी तैयार करनी है। मैंने इस कार्य हेतु आवेदन दिया तब वन विभाग द्वारा मुझे प्रशिक्षित किया गया। मैंने भारती जीविका महिला ग्राम संगठन से 20,000 रुपये कर्ज लिये और अपने पास जमा थोड़े पैसों को मिलाकर मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन थी उसमे मिटटी भरवाया एवं शेष पैसों से पौली पैक खरीदा। वन विभाग द्वारा फरवरी, 2020 में मुझे 20,000 पौधे उपलब्ध कराये गए एवं 88,000 रुपये उन पौधों के रख–रखाव हेतु मिले। मैंने उन पौधों की सिचाई एवं देख–भाल लगभग 7 महीने तक किया। अक्टूबर, 2020 में वन विभाग ने 16,500 पौधों को रुपये 11/– की दर से वापस ले लिया जिसमें वन विभाग द्वारा दी गयी प्रारंभिक राशि 88,000 रुपये को घटा लिया गया। शेष पौधों को मैंने 10–15 रुपये की दर पर दिसम्बर 2020 तक बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया में अगर खर्च को निकाल दे तो मुझे शुद्ध मुनाफा 1,30,000 रुपये का हुआ। यह जीवन में एक बड़ी पूंजी है। उन पैसों से मैंने अपने घर की मरम्मती करवायी, दरवाजा लगवाया और अब बेटी का अच्छे इंटर कॉलेज में दाखिला भी दिलवा दिया है। नर्सरी खुलने से मेरी किस्मत ही बदल गयी।

जल–जीवन–हरियाली अभियान से बदल रहा बिहार

पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार का अभिनव प्रयास

पर्यावरण संतुलन, पर्याप्त जल और हरित आवरण बढ़ाने के लिए बिहार में ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' की शुरूआत की गयी। हाल के दशकों में बिहार बाढ़ और सूखे का शिकार होता रहा है। इन समस्याओं के साथ मौसम में आ रहे बदलावों को देखते हुए राज्य में जल–जीवन–हरियाली योजना पर काम प्रारंभ किया गया। इसको मूर्त्त रूप प्रदान करते हुए वर्ष 2019 में गाँधी जयंती के 150वीं वर्षगांठ पर ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' की विधिवत् शुरुआत की गयी।

पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं पर्यावरण के प्रति अपनी गंभीर सोच को अमली जामा पहनाने एवं मिशन मोड में इसे पूरा करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन का गठन किया गया। मिशन राज्य के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में संचालित है। तीन वर्षों की अवधि में 'जल–जीवन–हरियाली मिशन' द्वारा 24 हजार 524 करोड़ खर्च किया जाना है। जल–जीवन–हरियाली योजना की सफलता के लिए ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, लघु जल संसाधन, नगर विकास, पीएचईडी, कृषि, भवन, जल संसाधन, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ऊर्जा एवं सूचना एवं जनसंपर्क सहित 15 विभाग शामिल हैं।

स्वच्छ व संतुलित पर्यावरण के लिए पृथ्वी पर 33 प्रतिशत हरियाली जरूरी है। राज्य सरकार प्रथम चरण में प्रदेश का हरित आवरण क्षेत्र 17 प्रतिशत या इससे ज्यादा करने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है जिसके लिए योजना तैयार है। जीविका द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मनरेगा के साथ समन्वय कर स्वयं सहायता समूह सदस्यों के माध्यम से 197 नर्सरी विकसित की गयी तथा 72 लाख फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए गए हैं।

योजना के तहत आहर, पोखर, छोटी नदियों, पुराने कुंओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। चापाकल, कुंआ सरकारी भवन में जल संचय के लिए रेन वाटर हारवेस्टिंग का कार्य किये जाने की योजना है। छोटी नदियों, नालों और पहाड़ी क्षेत्र में चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है। ऊर्जा के सीमित क्षेत्रों को देखते हुए वैकल्पिक स्रोतों और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के तहत ई रिक्शा, सोलर लैम्प, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग जैसे कार्यों तथा सीएनजी चालित वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर भी पौधारोपण किया जा रहा है।

दिनांक 12 जनवरी 2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत नव–सृजित/विकसित सार्वजनिक जलाशयों के रख–रखाव एवं प्रबंधन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्री ब्रज किशोर पाठक – विशेष कार्य पदाधिकारी
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, बक्सर
- श्री विकाश राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री अभिजीज मुखर्जी – यंग प्रोफेशनल
- श्री मनीष कुमार – प्रबंधक संचार, वैशाली